(ख) इनमें से कितने पत्रों की जांच की गयी है और कितने पत्रों के उत्तर दे दिये गये हैं तथा शेष कितने पत्र उत्तर के लिये लम्बित पड़े हैं; और

(ग) शेष पत्रों की जांच कर उनका उत्तर कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबदुल गफूर अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के मामलों में कमी

961. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन करने के संबंध में पकड़े गये एवं गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा शिकायत किये जाने के बावजूद गिल एंड कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनी के विरुद्ध फेरा के अधीन विनिर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है ?

वित्त मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी हां, विभिन्न उदारीकरण योजनाओं अर्थात् सोने का आयात, ट्रेड लेखों पर पूर्ण परिवर्तनीयता, चांदी का आयात लागू करने के परिणामस्वरूप कमी आयी है।

(घ) गिल एण्ड कम्पनी तथा उसकी सहयोगी कम्पनी के विरुद्ध जांच-पड़ताल करने के दौरान कानून के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है।

U. P. Government's Request for Central Assistance

962. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government of Uttar Pradesh has requested the Central Government to provide an assistance of Rs. 180 crore for completing the projects of irrigation, power and public works etc.;

(b) if so, whether this assistance has been approved by the Central Government; and

(c) the details thereof and if not, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Government of Uttar Pradesh has requested the Central Government for providing assistance for Anpara 'B' Project amounting to Rs. 156 crores for 1992-93 and Rs. 138.50 crores for 1993-94.

(b) and (c) The request of the State Government is under consideration of the Government of India.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अंतर्गत खाते

963. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के संचालन मण्डल ने चालू वर्ष 1993 के तुलन-पत्र में करीब 6 करोड़ रुपये की संदिग्ध एवं अशोध खाते की रकम का किसी अन्य जगह प्रावधान करके लाभ और जमा राशि को बढ़ाकर लगभग

44 करोड़ रुपये दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बैंक के तुलन-पत्र तथा वार्षिक विवरण-पत्रों की जांच किसी अन्य अभिकरण द्वारा कराने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह सच है कि निदेशक मंडल द्वारा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही लाभ तथा हानि संबंधी विवरण स्वीकार कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार बैंक के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Irregularities in Banks

964. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Banking Operation and Development (DBOD) of the Reserve Bank of India have come across large scale irregularities in discounting of bills and advances by the Indian as well as foreign banks;

(b) if so, what are the names of banks (both Indian & Foreign) in which irregularities have been detected and what are the details thereof;

(c) what are the details of guidelines issued by RBI in this regard; and

(d) what action Government/RBI have taken in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) RBI have come across instances of irregular discounting of bills by banks. It would not be in the public interest to disclose the names of the banks where irregularities have been observed by Reserve Bank of India (RBI). However, details of the more common irregularities are given in Statement I (*See* below).

(c) Detailed instructions were issued by RBI in this regard on 27th July, 1992 in continuation of earlier instructions. A copy of these instructions. are given in statement II (*See* below).

(d) All cases of irregularities observed by RBI during inspection are taken up with individual banks for necessary rectification, including staff accountability. The bank's comments are called for and thereafter all findings are discussed by RBI's top management with the bank officials. RBI uses every forum to impress upon the bank executives the need for thorough and proper appraisal of credit proposals.

Statement

(a) Banks have been providing bill finance to large borrowers (whose working capital requirements are met by a consortium of banks) outside the consortium without informing the lead bank and the other consortium members.

(b) With a view to providing temporary financial accommodation to certain companies, banks have been drawing bills on such constituents and they themselves are discounting such bills and availing of rediscounting facilities against such bills. At times, such bills have been guaranteed or co-accepted by another bank.

(c) Banks have provided additional finance by way of bill limits covering sales of goods to certain industrial houses outside consortium aggrangements in the result, the proceeds of bills realised have been unavailable to the banks providing production finance towards reduction of the level of outstanding credit to those borrowers.